MATION		::आयुक्त (अपील्स) का का 0/0 THE COMMISSIO			
		0/0 THE COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2 nd Floor, GST Bhavan		A tothe	
		रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road			
राजकोट / Rajkot - 360 001					
Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: cexappealsrajkot@gmail.com					
रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-					
क	अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.		मूल आदेश सं /	दिनांक/	
	V2/19/GDM/2	2019	O.I.O. No. Refund Order No. 2	Date 19-07-2018	
ख	अपील आदेश संख्या	(Order-In-Appeal No.):			
KCH-EXCUS-000-APP-093-2019					
	आदेश का दिनांक / Date of Order:	22.10.2019	जारी करने की तारीख / Date of issue:	23.10.2019	
श्रीगोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /					
-	Passed by Shri. Gopi Nath, Commissioner (Appeals),Rajkot				
ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,				
घ	Rajkot / Jamnagar / Gandhidham : ज्ञ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-				
	Gujarat NRE Coke Ltd(Steel Division), Village, Lunava Taluka Bhachau, Kutch-370140				
	इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्न्स्रिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.				
(A)	के अंतर्गेत एवं वित्त अ	सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/			
(i)	Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-				
(4)		र्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट लॉक न 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए 1/			
(1)	Delhi în all matte	The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.			
(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/				
(iii)	To the West regional bench of Customs. Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at. 2 nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संसम्म करें। निर्धारित शुल्क का मुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/				
(B)	अपीलीय न्यायाधिक तहत निर्धारित प्रपत्र (एण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, S.T5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी	iled in quadruplicate in form EA-3 / as shall be accompanied against one 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/ 5 Lac. to 50 Lac and above 50 strar of branch of any nominated pub tor bank of the place where the bench ompanied by a fee of Rs. 500/- ,1994 की धारा 86(1) के अंतगेत सेवाकर निय एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की	मवाली, 1994, के नियम 9(1) के गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न	
	जुर्माना,रुपए 5 लाख रुपये अथवा 10,000 शाखा के सहायक रजि का भुगतान, बैंक की आवेदन-पत्र के साथ 5	या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 ला)/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की रिटार के नाम से किसी भी सावजिनक उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधि 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा क	कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँ ख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है त प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, र क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक झुफ्ट दवारा ात अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । रना होगा ।/	ो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए	
	The appeal under in quadruplicate accompanied by accompanied by Rs. 5 Lakhs or 1 than five lakhs demanded & per Assistant Regist situated. / Appli	r sub section (1) of Section 86 in Form S.T.5 as prescribes a copy of the order appeale a fees of Rs. 1000/- where the ess. Rs.5000/- where the am but not exceeding Rs. Fifty naity levied is more than fifty rar of the bench of nominate (cation made for grant of stay s	5 of the Finance Act, 1994, to the Apped d under Rule 9(1) of the Service Tax d against (one of which shall be cer- he amount of service tax & interest demand Lakhs, Rs.10,000/- where the amoun Lakhs, rupees, in the form of crossed d Public Sector Bank of the place whe shall be accompanied by a fee of Rs.50	Ellate Tribunal Shall be filed Rules, 1994, and Shall be inied copyl and should be manded & penalty levied of ed & penalty levied is more at of service tax & interest bank draft in favour of the gre the bench of Tribunal is D/	

· ·

े. संस्

C

(i)

(ii)

वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में

उपायुक्त, कन्द्रीय उत्पाद राज्य, प्रधान, जार का का कि कन्द्रीय उत्पाद राज्य, जार कि के क्रिंग करनी होगी । / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944

अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जूर्माना विवादित है, का भूगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपएँ से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम **(i)**
- सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
- सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)

बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include : (i) amount determined under Section 11 D; (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken; (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules - provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C)

भारत सरकार कोपूनरीकण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रयमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद माग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से अंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंडार गृह में दूसरे अंडार गृह परगमन के दौरान, या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के (ii) मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

- यदि उत्पाद शुल्क का भगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित अधिनियम (न. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए । जहाँ संलग्न रकन एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो (vi) तो रूपये 1000 -/ का भुगता किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं।/ For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.m.



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Gujarat NRE Coke Ltd. (Steel Division), Village Lunava, Tal Bhachau, Kutch (hereinafter referred to as 'Appellant') has filed the present appeal against Order-In-Original No. Refund order No. 02 dated 19.07.2018 (hereinafter referred to as 'the impugned order'), passed by the Assistant Commissioner, CGST Division-Anjar Bhachau. (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. The facts of the case in brief, are that during the course of audit, on verification of records, it was noticed that the said appellant has wrongly availed cenvat credit of service tax for the year 2008-09 amounting to Rs. 15,61,009/- and for the F.Y. 2009-10 amounting to Rs. 24,64,805/-. A SCN No. V.72/AR-Kharirohar/ADC/287/2013 dated 17.12.2013 was issued to the appellant for recovery of wrongly availed and utilized cenvat credit and same was confirmed vide order in original No. 06/JC/RKT/2014-15 dated 30.09.2014 and confirmed recovery of wrongly availed cenvat credit of service tax to the tune of Rs. 40,25,814/- and also imposed the penalty of Rs. 40,25,814 under Rule 15 of Cenvat Credit Rules, 2004. Being aggrieved the appellant filed an appeal before the appellate authority who vide OIA No. KCH-EXCUS-000-APP-021-15-16 dated 31.07.2015 rejected the appeal filed by the appellant and upheld the impugned order.

2.1 The appellant preferred appeal before the CESTAT, Ahmedabad against the said OIA and appellant also paid pre-deposit of Rs. 7,04,600/-. The CESTAT vide order No. A/13248/2017 dated 23.10.2017 set aside the impugned OIA and allow the appeal filed by the appellant. Accordingly, the appellant filed for refund of pre-deposit of Rs. 7,04,600/- on 09.07.2018. The adjudicating authority vide impugned refund order rejected refund on the basis of that the appellant is under liquidation process and NCLT has appointed Resolution Professional followed by Liquidator Shri Sumit Binani and subject refund claim was filed by the authorized signatory of the company instead of liquidator and same is in-admissible as per Section 33(5) of the insolvency and bankruptcy code, 2016.

3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant preferred the present appeal, interalia, on the following grounds:

 (i) The impugned order passed by the lower adjudicating authority is illegal and should be quashed and set aside. Appellant submitted that CESTAT vide Order No. A/13248/2017 dated 23.10.2017 has allowed the appeal and set aside the Order-in-Appeal No. KCH-EXCUS-000-APP-021-15-16 dated 31.07.2015 issued by the Appellate Authority upholding OIO No.

06/JC/BKS/2014-15 dated 30.09.2014 confirming recovery of Cenvat Credit to the tune of Rs. 40,25,814/-. Further, appellant had paid pre-paid deposit of Rs. 7,04,600/- as per Section 35F of the Central Excise Act, 1944.

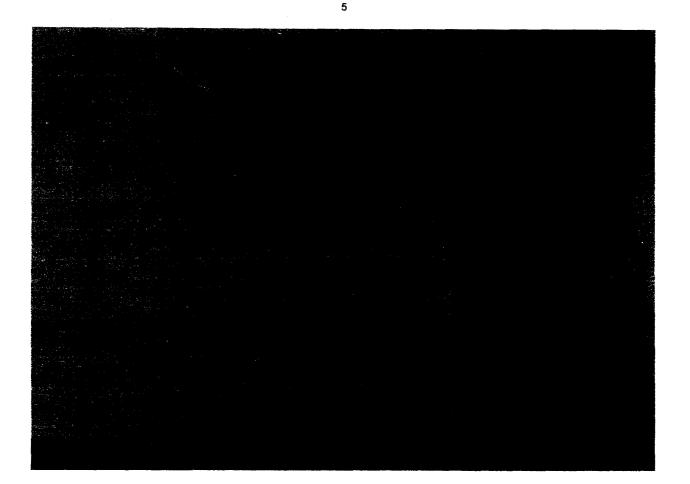
- (ii) CBEC vide circular No. F.No. 275/37/2K-CX.8A dated 02.01.2002 and circular No. 802/35/2004-CX dated 08.12.2004 and circular No. 984/08/2014-CX dated 16.08.2014 regarding return of deposit in the event the appellant succeeds in appeal or in matter is remanded for fresh adjudication, pre-deposit amount is required to be refunded based on simple letter with self attested copy of such order and copy of challans evidencing payment.
- (iii) Adjudicating authority rejected refund application on the ground mentioned at point no. 14 of refund order No. 02 which states that "according to Section 33(5), 34(1) and 34(2) of the insolvency and Bankruptcy Code 2016 the claim was required to be filed by the Liquidator with the prior approval of the Adjudicating Authority which hasn't happened. Instead the claim was filed by the Claimant without prior approval or intimation to the Liquidator or NCLT"
- (iv) Further, on receipt of the Refund Order, the appellant had submitted letter dated 01.08.2018 has authorized Mr. Amit Agarwal for filing refund of Pre deposit arising out of CESTAT Order; he also informed that he is not required to take any prior approval for the purpose of claiming such refund as Regulation 39 of the IBBI (Liquidation process) Regulations, 2016 empowers him to recover the monies due of the company under liquidation in a time bound manner.

4. Personal hearing in the matter was attended to by Shri Pradyot K Chatopadhyay, General Manager Commercial and Shri Amit Agarwal, AGM Commercial, who reiterated Grounds of Appeal and submitted that their appeal may be decided on the basis of above facts and legal position.

5. In light of the above facts, I find that the appeal first needs to be decided on the limitation of time. Ongoing through the facts of the case, I find that the appeal has been filed beyond 90 days of the receipt of the impugned order. The matter regarding delay of receipt of the impugned order was taken up with the Jurisdictional Central Goods & Service Tax Division, Anjar-Bhachau Division through email dated 15.10.2019 who reported that the impugned order was dispatched through registered post on dated 25.07.2018 as is evident from the receipt of postal department.



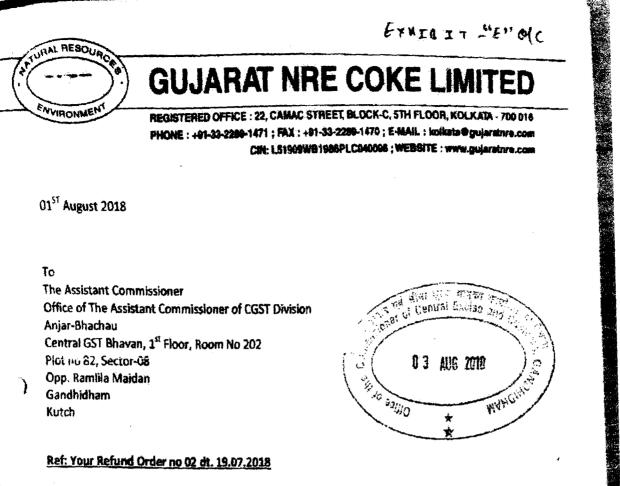
.



5.1 Further, appellant in the grounds of appeal at para no. 14.9 has mentioned that "However, on receipt of the Refund Order No. 02 dated 19.07.2018 issued on 23.07.2018 by the Assistant Commissioner, CGST & CEX Division, Anjar-Bhachau rejecting our refund application of Rs. 7,04,600/-, the appellant submitted the letter dated 01.08.2018, duly acknowledge by department on 03.08.2018 for restoration of Refund Application on the basis of letter dated 01.08.2018 issued by Mr. Sumit Binani, Liquidator of the appellant".

5.2 Further, in above referred letter dated 01.08.2018, the appellant has clearly mentioned that "we are in receipt of your letter F.No. V/35-09/Refud/2018-19/76 dated 23.07.2018 issued for refund order No. 02 dated 19.07.2018 whereby you have rejected our refund application on the ground as mentioned in point no. 14 of the said order". The copy of the above letter is reproduced herewith and same is evident that the appellant has received said OIO on or before 01.08.2018 and the present appeal has been filed on 11.02.2019 after lapse of 194 days from the receipt of impugned order.





6

Sub: Request for restoration of Refund Application

धेत्र होत्य

Dear Sir

Ď

We are in receipt of your letter no F.NO. V/35-09/Refund/2018-19/76 dt. 23.07.2018 issued for refund order no 02 dt. 19.07.2018 whereby you have rejected our refund application on the ground as mentioned in point no 14 of the said order which states that "According to Section 33(5), 34(1) and 34(2) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 the claim was required to be

) filed by the Liquidator with the prior approval of the Adjudicating Authority which hasn't happened. Instead the claim was filed by the claimant without prior approval or intimation to the Liquidator or NCLT, Kolkata which is the adjudicating authority in the matter. Therefore, I find that it is a clear violation of the Section 33(5), 34(1) and 34(2) of the insolvency and Bankruptcy Code 2016 and thus the claim is in-admissible".

In this regard we would like to inform you that Liquidator (Mr. Sumit Binani) of the company has authorised Mr. Amit Agarwal (Pan no ARRPA5098A) vide his letter dt. 01.08.2018 for filing refund of Pre deposit arising out of CESTAT Order no A/13248/2017 DT. 23.10.2017. He also informed that he is not required to take any prior approval for the purpose of claiming support.

Office : NRE_HOUSE, 45-A, Sere Section Road, Januager - 261 986 ; Phone : +91-280-2556785 / 1727 ; Fex : +91-280-2555716 ; E-mail: : januagendigujarative.com Vitorice : Vitince : Diameterative, Jam-Maambhalle Bigujarative.com

Signator

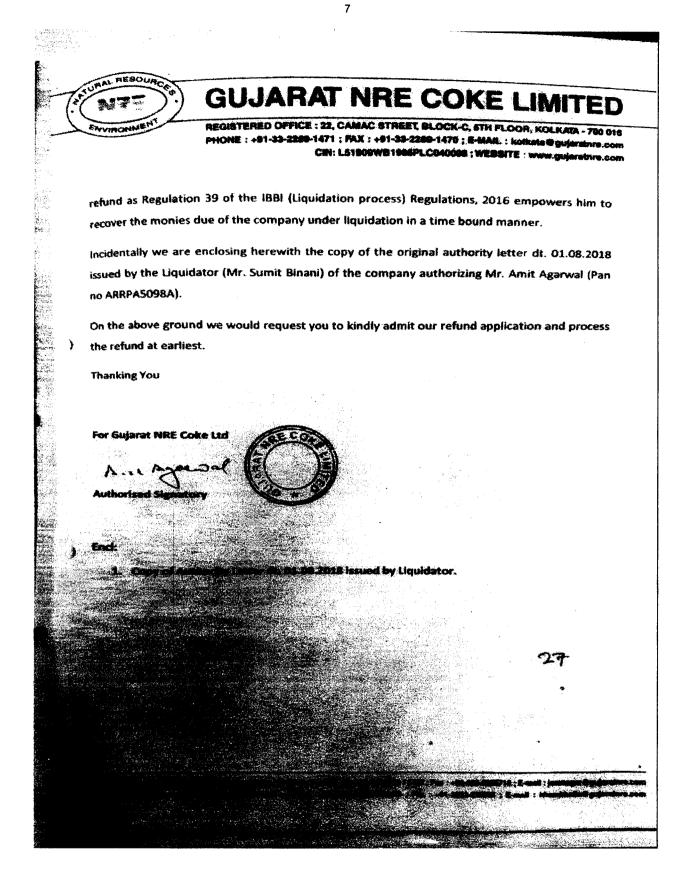
COXE

NNE

32

E GA

10 ju



06. The Commissioner (Appeals), as per proviso to Section 35(1) of the Central Excise Act, is vested with power to condone delay of maximum up to thirty days, over and above the normal period of sixty days, albeit on reasonable cause being shown. The present appeal is filed beyond stipulated time limit of 90 days provided under the statute. I find no reason to entertain such an appeal beyond power given to me. Therefore, I am of the considered view that such an appeal is liable to be dismissed on the ground of limitation alone. Accordingly, I reject the present appeal on the ground of limitation of time in filing appeal.

७. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9

7. The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.

सत्यापित २ूर्नेज्ने प् संजय शेठ अधीक्षक (अपील्स)

jure

(Gopi Nath) ν Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To,

M/s. Gujarat NRE Coke Ltd. (Steel Division), Village Lunava, Tal Bhachau, Kutch

Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
- 2. The Commissioner, GST & Central Excise, Kutch Commissionerate, Gandhidham.
- 3. The Assistant Commissioner, CGST & Central Excise Division-, Anjar-Bhachau.

4. Guard File.

